PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 233
दि. 27.05.2026, बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बंगाल की राजनीति में भूचाल: चुनावी हार के बाद टीएमसी में टूट और असंतोष की चर्चाओं ने बढ़ाई सियासी हलचल

कोलकाता में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक असंतोष की चर्चाएं तेज हो गई हैं। राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल उस समय बढ़ गई जब यह खबर सामने आने लगी कि पार्टी के कई सांसद कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और बड़े स्तर पर दल-बदल की संभावना पर चर्चा चल रही है। राजनीतिक गलियारों में यह भी दावा किया जा रहा है कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 29 सांसदों में से करीब 12 सांसदों का एक समूह भाजपा में शामिल होने या उसके समर्थन में जाने की रणनीति पर विचार कर रहा है। हालांकि इन दावों की अभी तक किसी भी स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस चर्चा ने राज्य और राष्ट्रीय राजनीति दोनों में नई बहस को जन्म दे दिया है।

सूत्रों के अनुसार इस संभावित राजनीतिक बदलाव के पीछे संगठनात्मक असंतोष, नेतृत्व शैली को लेकर मतभेद और पार्टी के भीतर निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दों को कारण बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ सांसदों के बीच यह विचार उभर रहा है कि यदि एक बड़ा समूह एक साथ पार्टी छोड़ता है तो दल-बदल विरोधी कानून के प्रभाव से बचा जा सकता है। इसी रणनीति के तहत 19 से 20 सांसदों को एक साथ लाने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में की जा रही है, ताकि कानूनी बाधाओं से बचते हुए एक वैकल्पिक राजनीतिक रास्ता अपनाया जा सके।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस तरह का कोई बड़ा बदलाव वास्तव में होता है तो यह न केवल तृणमूल कांग्रेस के लिए बल्कि पश्चिम बंगाल की

राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। लोकसभा में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति बनी हुई है और यदि तृणमूल के सांसदों का कोई बड़ा समूह पार्टी बदलता है तो संसद में शक्ति संतुलन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि ऐसे दावे अक्सर राजनीतिक दबाव और रणनीति का हिस्सा भी होते हैं, इसलिए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इस बीच यह भी चर्चा में है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद राज्यसभा में भी भाजपा के संपर्क में हैं। यदि यह घटनाक्रम आगे बढ़ता है तो यह केवल लोकसभा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। भाजपा की रणनीति को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह विपक्षी दलों के भीतर असंतोष का लाभ उठाकर अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश में है।

इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच मंगलवार को कोलकाता में एक प्रशासनिक बैठक ने नई चर्चा को जन्म दिया, जब तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार और कुछ अन्य विधायकों की उपस्थिति को लेकर सवाल उठने लगे। बताया जा रहा है कि यह बैठक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें देगंगा और स्वरूपनगर क्षेत्र के विधायकों की मौजूदगी भी सामने आई। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इसे पार्टी लाइन से अलग एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस बैठक को प्रशासनिक बताया गया है, लेकिन इसमें विभिन्न दलगत नेताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। विपक्षी दल इस घटनाक्रम को लेकर अलग-अलग व्याख्याएं कर रहे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की आवाजें भी खुलकर सामने आने लगी हैं। पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा कर पार्टी की मौजूदा स्थिति और आंतरिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति की तुलना अस्थिर परिस्थितियों से की, जिससे राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है।

सुखेंदु शेखर रॉय की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पार्टी पहले से ही नेतृत्व, संगठन और रणनीति को लेकर कई तरह के सवालों का सामना कर रही है। उनके बयान को पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि जब किसी दल के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तो यह आंतरिक संकट का संकेत माना जाता है, हालांकि इसका वास्तविक राजनीतिक प्रभाव समय के साथ ही स्पष्ट होता है।

तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी तक इन सभी चर्चाओं और दावों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पार्टी नेतृत्व लगातार संगठन को एकजुट बनाए रखने की कोशिश में जुटा है और माना जा रहा है कि शीर्ष स्तर पर बैठकों का दौर भी जारी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही तीव्र प्रतिस्पर्धा और अप्रत्याशित बदलावों के लिए जानी जाती रही है। ऐसे में दल-बदल और आंतरिक असंतोष की खबरें नई नहीं हैं, लेकिन जब ये चर्चाएं बड़े स्तर पर सांसदों की संख्या से जुड़ने लगती हैं, तो उनका राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। फिलहाल यह पूरा मामला चर्चाओं, अटकलों और राजनीतिक संकेतों के बीच घूम रहा है। वास्तविक तस्वीर क्या होगी, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन इतना तय है कि इस घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति में एक बार फिर अनिश्चितता और संभावनाओं दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया है, जिसका असर राज्य की राजनीतिक दिशा पर गहरा पड़ सकता है।

युद्धविराम वार्ता के बीच फिर भड़का तनाव, अमेरिका-ईरान टकराव ने पश्चिम एशिया को संकट के मुहाने पर पहुंचाया

वॉशिंगटन और तेहरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। युद्धविराम और कूटनीतिक बातचीत की कोशिशों के बीच मंगलवार को अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स तथा होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरानी नौकाओं पर सैन्य कार्रवाई कर दी। अमेरिकी सेना ने इन हमलों को "आत्मरक्षा" के तहत की गई कार्रवाई बताया, जबकि ईरान ने इसे सीजफायर भावना का उल्लंघन करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात के बीच इस घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र को फिर से व्यापक सैन्य संघर्ष के खतरे के करीब ला खड़ा किया है।

अमेरिकी सेना की ओर से जारी जानकारी के अनुसार हमले उन ठिकानों और नौकाओं पर किए गए, जिन्हें अमेरिकी बलों के लिए संभावित खतरा माना जा रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिन्स ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों और युद्धपोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक थी। उन्होंने दावा किया कि कुछ ईरानी नौकाएं समुद्री मार्गों में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रही थीं, जिससे अंतरराष्ट्रीय नौवहन और अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को खतरा पैदा हो सकता था।

इन हमलों का सबसे बड़ा असर दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास क्षेत्र में देखा गया, जहां ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमलों में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी के चार जवान मारे गए। बंदर अब्बास सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार गुजरता है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार पर सीधा असर डाल सकता है।

घटनाक्रम की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यह हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ईरान के साथ बातचीत "अच्छे तरीके से आगे बढ़

रही है।" ट्रंप प्रशासन लगातार यह दावा करता रहा है कि वह युद्ध नहीं बल्कि नियंत्रित दबाव और कूटनीति के जरिए ईरान को परमाणु और सैन्य गतिविधियों पर सीमित करना चाहता है। लेकिन ताजा सैन्य कार्रवाई ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास अभी भी बेहद गहरा है।

ईरान ने अमेरिकी हमले के तुरंत बाद तीखी प्रतिक्रिया दी। ईरानी सेना के प्रवक्ता अबोलफजल शेखरची ने कहा कि यदि अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो ईरान पहले से कहीं अधिक कठोर और व्यापक जवाब देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगला जवाब केवल क्षेत्रीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका दायरा और प्रभाव कहीं अधिक बड़ा हो सकता है।

तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान की ओर से दावा किया गया कि उसकी सेना ने अमेरिकी एमक्यू-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसियों और आईआरजीसी के हवाले से कहा गया कि यह ड्रोन ईरानी हवाई क्षेत्र में घुस आया था और सुरक्षा बलों ने उसे निशाना बनाया। इसके साथ ही ईरान ने यह दावा भी किया कि उसने एक अमेरिकी एफ-35 लड़ाकू विमान पर गोलीबारी की। हालांकि अमेरिकी पक्ष की ओर से इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

विश्लेषकों का मानना है कि ड्रोन गिराए जाने का दावा केवल सैन्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। ईरान लंबे समय से यह दिखाने की कोशिश करता रहा है कि वह अमेरिकी निगरानी और सैन्य तकनीक को चुनौती देने में सक्षम है। दूसरी ओर अमेरिका यह स्पष्ट करना चाहता है कि वह खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी और समुद्री सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का जोखिम स्वीकार नहीं करेगा।

इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने भी बेहद तीखा बयान दिया। हज यात्रा के अवसर पर दिए गए संदेश में उन्होंने कहा कि अब पश्चिम एशिया अमेरिकी सैन्य अड्डों के लिए "सुरक्षित ढाल" नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि समय बदल चुका है और क्षेत्र के देश अब अमेरिका की सैन्य रणनीतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। खामेनेई ने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील करते हुए फिलिस्तीन और अल-अक्सा मस्जिद के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। ईरान की ओर से लगातार आ रहे इन बयानों को केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं माना जा रहा, बल्कि यह संकेत माना जा रहा है कि तेहरान क्षेत्रीय गठबंधनों और वैचारिक समर्थन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। खासकर ऐसे समय में जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और इजरायल के साथ उसके रिश्ते लगातार चर्चा में हैं।

दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर भी नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की प्राथमिकता यह है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में नष्ट किया जाए। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि यूरेनियम को अमेरिका लाकर नष्ट करने की बजाय किसी स्वीकार्य अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के तहत ईरान या किसी अन्य स्थान पर नष्ट किया जा सकता है।

ट्रंप का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले वह बार-बार कहते रहे थे कि किसी भी संभावित समझौते की सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपे। अब उनके रुख में आए इस बदलाव को कूटनीतिक लचीलेपन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

क्या सूरत नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को अधिकारियों के घरेलू कामों में लगाया जा रहा है? कर्मचारी संघ का गंभीर आरोप

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

सूरत नगर निगम के कर्मचारियों ने इस अवैध प्रथा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जब चौंकाने वाले खुलासे हुए कि सूरत नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को अधिकारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों के घरों में निजी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि निगम के कुछ उच्च अधिकारी सफाई कर्मचारियों को अपने निजी आवासों में सफाई, खाना पकाने और घरेलू कामकाज के लिए नियुक्त कर रहे हैं। इन गतिविधियों के कारण निगम के मुख्य कार्यों में सफाई कर्मचारियों की कमी हो गई है और शेष कर्मचारियों पर काम का बोझ

बढ़ता जा रहा है।

महामंडल द्वारा लगाए गए मुख्य आरोपः अधिकारियों की चापलूसीः कुछ स्वच्छता निरीक्षकों (एसआई) पर सफाई कर्मचारियों से सब्जियां, दूध और अन्य निजी सामान मंगवाने का दबाव डाला जा रहा है ताकि अधिकारियों को खुश रखा जा सके। प्रशासनिक दुरुपयोगः लाखों रुपये का वेतन पाने वाले अधिकारियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों को निजी नौकरों की तरह इस्तेमाल करना अत्यंत अनैतिक और सरकारी नियमों के विरुद्ध है।

सेवानिवृत्त अधिकारियों के लाभः नगरपालिका के सेवानिवृत्त अधिकारी और उनके परिवार भी इस प्रकार की अवैध सेवा का लाभ उठा रहे हैं, जो जनता के कर धन का प्रत्यक्ष दुरुपयोग है। इस गंभीर मामले में सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव, उपाध्यक्ष किरित सिंह जे. वाघेला, महासचिव मोहम्मद इकबाल शेख, मंत्री हरीशभाई राठौड़ और वरिष्ठ नेताओं विजयभाई शेनमेरे और जयंतीभाई वाघेला ने सूरत नगर आयुक्त श्री एम. नागराजन जी को लिखित में कड़ा प्रतिवेदन दिया है।

फेडरेशन ने मांग की है कि इस प्रथा को तत्काल रोका जाए और इस तरह के कृत्य करने वाले अधिकारियों या खुफिया अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। अगर निकट भविष्य में इस प्रथा को नहीं रोका गया, तो फेडरेशन ने आंदोलन आयोजित करने की भी धमकी दी है।

समुद्री रास्ते से श्रीलंका भेजी जा रही थी अरबों की ड्रग्स खेप, ईडी के छापों से दक्षिण भारत में मचा हड़कंप

चेन्नई। दक्षिण भारत में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरै में कई अहम ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई समुद्री रास्ते से भारत से श्रीलंका तक नशीले पदार्थों की तस्करी और उससे जुड़े धन शोधन नेटवर्क की जांच के तहत की गई। ईडी की टीमों ने कई संदिग्ध कारोबारियों, हवाला ऑपरेटरों और कथित तस्करी नेटवर्क से जुड़े लोगों के परिसरों की तलाशी ली। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह केवल एक सीमित तस्करी गिरोह नहीं, बल्कि दक्षिण भारत से संचालित एक संगठित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है, जिसके तार समुद्री मार्गों, हवाला चैनलों और विदेशी आपराधिक गिरोहों तक जुड़े हो सकते हैं।

अधिकारियों के अनुसार यह पूरी कार्रवाई वर्ष 2024 में राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए दो बड़े मामलों के आधार पर की जा रही है।

इन मामलों में जॉन ब्रिट्टो नामक व्यक्ति और उसके सहयोगियों को मुख्य आरोपी माना गया है। ईडी को शक है कि ड्रग्स तस्करी से कमाई गई अवैध रकम को कई फर्जी कंपनियों, बैंक खातों और हवाला लेनदेन के जरिए सफेद बनाया जा रहा था।

जांच एजेंसियों के मुताबिक पहला मामला मार्च 2024 का है, जब डीआरआई मदुरै इकाई ने मन्नार की खाड़ी में एक संदिग्ध मछली पकड़ने वाली नाव को रोका था। तलाशी के दौरान नाव से करीब 99 किलोग्राम हशीश बरामद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 108 करोड़ रुपये आंकी गई थी। अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में बरामद नशीले पदार्थ यह संकेत देते हैं कि यह कोई स्थानीय स्तर का गिरोह नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन का हिस्सा था।

जांच में सामने आया कि रामिश, जानसन और प्रताप नामक तीन आरोपी मुख्य सरगना जॉन ब्रिट्टो के निर्देश पर इस खेप को समुद्री रास्ते से श्रीलंका पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। एजेंसियों का मानना है कि श्रीलंका को केवल ट्रांजिट प्वाइंट के रूप में इस्तेमाल किया जाना था और वहां से यह खेप अन्य अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तक पहुंचाई जा सकती थी। समुद्री सीमाओं का फायदा उठाकर इस प्रकार की तस्करी लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी हुई है।

मन्नार की खाड़ी को लेकर जांच एजेंसियां पहले भी सतर्क रही हैं, क्योंकि यह क्षेत्र भारत और श्रीलंका के बीच संवेदनशील समुद्री मार्ग माना जाता है। यहां छोटी मछली पकड़ने वाली नावों का इस्तेमाल कर तस्करी करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। कई बार तस्कर मछुआरों की आड़ में अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। यही वजह है कि डीआरआई, तटरक्षक बल और अन्य एजेंसियां लगातार इस इलाके में निगरानी बढ़ा रही हैं।

इसी दौरान सामने आया दूसरा मामला और भी चौंकाने वाला था। मार्च 2024 में ही मदुरै रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति के पास से भारी मात्रा में मेथामफेटामाइन बरामद की गई थी। अधिकारियों के अनुसार पी. प्रकाश नामक व्यक्ति के कब्जे से 37.64 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंथेटिक ड्रग बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 150 करोड़ रुपये आंकी गई। मेथामफेटामाइन को दुनिया के सबसे खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स में गिना जाता है। इसका इस्तेमाल नशे के अवैध अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी से बढ़ रहा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में बरामद ड्रग्स यह दर्शाती है कि तस्कर अब पारंपरिक नशीले पदार्थों के साथ-साथ अत्यधिक लाभ देने वाले सिंथेटिक ड्रग्स के कारोबार में भी तेजी से सक्रिय हो चुके हैं। ईडी को संदेह है कि दोनों मामलों के पीछे एक ही वित्तीय नेटवर्क काम कर रहा था। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि ड्रग्स कारोबार से कमाए गए करोड़ों रुपये किन माध्यमों से निवेश किए गए, किन लोगों को इसका लाभ मिला और क्या इस नेटवर्क के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान कई डिजिटल उपकरण, बैंकिंग दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जब्त की गई है। जांच एजेंसियों का यह भी मानना है कि ड्रग्स तस्करी का यह नेटवर्क केवल समुद्री मार्ग तक सीमित नहीं था, बल्कि रेलवे और सड़क मार्गों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। मदुरै रेलवे स्टेशन से हुई बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि तस्कर सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का उपयोग कर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे थे।

विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में ड्रग्स तस्करी की गतिविधियों में हाल के वर्षों में तेजी आई है। समुद्री सीमा की जटिल भौगोलिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की निकटता के कारण तस्कर इन क्षेत्रों को सुरक्षित मार्ग के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका के रास्ते दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्य देशों तक पहुंचने वाले नेटवर्क को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां पहले से सतर्क रही हैं।

ईडी अब इस पूरे मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत यह जांच कर रही है कि ड्रग्स कारोबार से अर्जित रकम को किन माध्यमों से वैध दिखाने की कोशिश की गई। अधिकारियों के अनुसार कई संदिग्ध बैंक खातों और संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस नेटवर्क के जरिए रियल एस्टेट, सोना कारोबार या अन्य व्यवसायों में निवेश किया गया था।

सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि इस नेटवर्क में कुछ स्थानीय कारोबारी, हवाला ऑपरेटर और विदेशी संपर्क भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल ईडी और डीआरआई की टीमें संयुक्त रूप से इस पूरे मामले की परतें खोलने में जुटी हुई हैं।

संपादकीय

गुरिंदरवीर की रिकॉर्ड दौड़ ने बढ़ाया राष्ट्रीय गौरव

एक प्रेरक कहावत है कि सुबह जिसकी हुई, सचमुच वो सारी रात नहीं सोया होगा। आज जब हम पंजाब के पुत्र गुरिंदरवीर सिंह की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी की बात कर रहे हैं तो हमें इस मुकाम तक पहुंचने के उसके संघर्ष को भी याद करना चाहिए। कोई भी कामयाबी रातों-रात नहीं मिलती। महज 10.09 सेकंड में सौ मीटर की रेस पूरी करने वाले गुरिंदरवीर सिंह ने, निस्संदेह नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर देशवासियों को गर्व करने का मौका दिया है। निर्विवाद रूप से उनके भारत के सबसे तेज धावक बनने की कहानी महज चंद घड़ियों की बदौलत नहीं नापी जा सकती। गांव की धूल से भरी सड़कों में उनका अभ्यास, प्रशिक्षण मैदानों में पसीने के साथ थका देने वाला सफर और संसाधन के अभावों से जूझकर ही वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वहीं इस कामयाबी में उनके परिवार का खामोश त्याग भी शामिल है, जो उनकी कामयाबी के बाद ही सुर्खियों में नजर आ पाया है। जालंधर के निकट स्थित पटियाल गांव के स्प्रिंट किंग गुरिंदरवीर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप में जब सौ मीटर की दौड़ 10.09 सेकेंड में पूरी की तो इस मुकाम तक पहुंचने वाले वे पहले भारतीय थे। एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। इस इतिहास को रचकर गुरिंदरवीर सिंह देश के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में शामिल हो गए हैं। इस सफलता का एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि इस कामयाबी के बाद वे स्वतः ही राष्ट्रमंडल खेलों में खेलने के हकदार हो गए हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में एक और पदक जीतने की उम्मीद फिर से जगा दी है। उल्लेखनीय है कि स्प्रिंट किंग गुरिंदरवीर का सौ मीटर की दौड़ पूरी करने का यह समय इस सीजन में एशिया का दूसरा सबसे तेज समय है। वे जापान के फुकुतो कोमुरो से महज .01 सेकेंड ही पीछे रहे हैं। विश्वास करना चाहिए कि भविष्य में गुरिंदरवीर सिंह नये मुकाम हासिल करेंगे।
यह विरोधाभास ही है कि जब कोई खिलाड़ी रिकॉर्ड कामयाबी हासिल करता है तो हम उसे पलक-पावड़ों पर बैठा देते हैं। मान-सम्मान और पुरस्कार देते हैं। लेकिन यदि छोटी उम्र में ही प्रतिभा को पहचान करके उसे पर्याप्त संसाधन व प्रशिक्षण प्रदान करें तो देश में कई गुरिंदरवीर तैयार हो सकते हैं। गुरिंदरवीर सिंह की इस कामयाबी के पीछे कई प्रेरणादायक कहानियां भी निहित हैं। उनका मानवीय पहलू हमारे समाज की सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। उनके पिता ने अपने बेटे को दौड़ के अभ्यास हेतु भेजने के लिये किश्तों में एक पुराना स्कूटर खरीदा था। जो बताता है कि एक तरफ क्रिकेट खिलाड़ियों पर लाखों-करोड़ों वारे जाते हैं तो दूसरी ओर परंपरागत खेलों से जुड़े खिलाड़ियों का संघर्ष कितना बड़ा है। वहीं गुरिंदरवीर सिंह को तराशने-निखारने की यात्रा में भारतीय नौसेना के योगदान को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जिसने गुरिंदरवीर सिंह को ट्रैक पर उत्कृष्ट सफलता हासिल करने हेतु संबल दिया। निस्संदेह, गांव-कस्बों से निकलने वाली प्रतिभाओं की कामयाबी के पीछे सीमित संसाधनों वाले माता-पिता के दृढ़ संकल्प और त्याग की कहानी छिपी रहती है। गुरिंदरवीर सिंह जैसे राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी के पीछे एक परिवार शिद्दत के साथ खड़ा होता है, जो उसके सुनहरे भविष्य के लिये अपनी सुख-सुविधा, बचत व आर्थिक सुरक्षा तक त्याग कर देता है। गुरिंदरवीर सिंह के दिल में गांव और साधारण परिवारों में पले-बढ़े बच्चों के संघर्ष के प्रति खासा सम्मान है। वे उन हजारों नवोदित खिलाड़ियों के लिये प्रेरणापुंज हैं जो अपनी पृष्ठभूमि वाले एक खिलाड़ी को राष्ट्रीय फलक पर चमकता देख रहे हैं। निश्चय ही इस कामयाबी से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही वजह है कि इस ऐतिहासिक कामयाबी से पहले जालंधर की महिला खिलाड़ियों से उनका संवाद बेहद सहज-सरल व प्रेरणादायक था कि तुम्हें भी एकदिन यहां पहुंचना है। निश्चय ही उनका यह कथन नवोदित प्रतिभाओं में नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। निस्संदेह, विगत में भी पंजाब ने कई ऐसे खेल नायकों को जन्म दिया, जिन्होंने अभावों से जूझते हुए दृढ़ संकल्प से कामयाबी की नई इबारत लिखी। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह से लेकर जालंधर एक्सप्रेस गुरिंदरवीर की कामयाबी उसकी गवाह है। जो नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने को प्रेरित करती है।

ऊर्जा की नई किरण भारत-ओमान समुद्री पाइपलाइन

> मिडिल-ईस्ट-इंडिया डीप-वाटर पाइपलाइन अरब सागर के नीचे लगभग 2,000 किलोमीटर तक लंबी होगी, जो ओमान को भारत के गुजरात तट से जोड़ेगी। इस परियोजना से भारत को ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर से गैस आपूर्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

होर्मुज़ जलसंधि का रास्ता बंद होने और भारत में ऊर्जा-संकट के बादल गहराने से जुड़ी खबरों के बीच एक खबर को ज्यादा सुर्खियां नहीं मिल पाईं कि भारत, गहरे समुद्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना पर विचार कर रहा है, जो हमें ओमान से जोड़ेगी। भारत सरकार ने अब इस पर तेजी से काम करना शुरू किया है।
हाल में कुछ मीडिया स्रोतों ने पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारियों को उद्धृत करते हुए खबर दी है कि मंजूरी मिली, तो करीब 4.8 अरब डॉलर की लागत से बनने वाली परियोजना खाड़ी क्षेत्र से निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। परियोजना को समय से हरी झंडी मिली, तब भी इसे पूरा होने में पांच से सात साल लगेंगे। उसके पहले इसके सभी आर्थिक और तकनीकी पहलुओं पर विचार करना भी ज़रूरी होगा।
सौ साल से ज्यादा समय से इसकी परिकल्पना चल रही है। इस पर यूपीए सरकार के दौर में भी बात चली थी। ओमान की वेबसाइट 'मस्कट डेली' की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार नई दिल्ली स्थित निजी क्षेत्र के कंसोर्शियम साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज (सेज) द्वारा प्रस्तुत पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पर विचार कर रही है, जो समुद्र तल की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए 'टेस्ट-सेक्शन' बिछा रहा है।
'सेज' ने प्रस्तावित मार्ग पर लगभग 3,000 मीटर परीक्षण पाइपलाइन बिछाकर प्रारंभिक चरण का तकनीकी सत्यापन कर लिया है, जिस पर लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह पाइपलाइन इंजीनियरों के लिए चुनौती भी होगी, क्योंकि कुछ जगहों पर यह करीब साढ़े तीन किलोमीटर तक की गहराई पर बिछानी पड़ेगी, जो अब तक समुद्र के नीचे बिछाई गई दुनिया की किसी भी पाइपलाइन की तुलना में चार गुना अधिक गहरी होगी।
इस अध्ययन का उद्देश्य समुद्र तल

की स्थितियों का आकलन करना और इंजीनियरिंग संभावनाओं की पुष्टि करना है। संभावना है कि भारत का पेट्रोलियम मंत्रालय, सरकारी कंपनियों गेल, इंजीनियर्स इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देगा। रिपोर्ट सकारात्मक हुई, तो ओमान के साथ गैस आपूर्ति, वित्तपोषण और परियोजना कार्यान्वयन पर औपचारिक बातचीत का रास्ता खुलेगा।
पश्चिम एशिया से भारत तक समर्पित पाइपलाइन बनी, तो हम किसी ट्रांज़िट देश या समुद्री अवरोध बिंदु पर निर्भर नहीं रहेंगे और किफायती लागत पर गैस की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी। मिडिल-ईस्ट-इंडिया डीप-वाटर पाइपलाइन (एमईआईडीपी) अरब सागर के नीचे लगभग 2,000 किलोमीटर तक लंबी होगी, जो ओमान को भारत के गुजरात तट से जोड़ेगी। इस परियोजना से भारत को ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर से गैस आपूर्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
वर्ष 2025 में भारत के एलएनजी आयात का लगभग दो-तिहाई हिस्सा होर्मुज़ जलसंधि से होकर गुजरा था। इस साल फरवरी के अंत में होर्मुज़ संकट शुरू होने के बाद, वैश्विक एलएनजी आपूर्ति में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जिससे कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। इस गिरावट के कारण भारत के उर्वरक संयंत्रों, बिजलीघरों और उद्योगों की आपूर्ति में अचानक लगे झटकों ने चिंता पैदा की है। खनिज तेल की ऊंची कीमतों ने आयात लागत को पहले ही बढ़ा दिया है।
इस पृष्ठभूमि में, टैंकरों पर निर्भरता को कम करने और प्राकृतिक गैस का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए दशकों पुरानी इस परियोजना को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 31 मिलियन मानक घन मीटर (एमएमएससीएमडी) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होने की उम्मीद है। वर्तमान राष्ट्रीय गैस खपत लगभग 190 से 195 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन है, जो औद्योगिक और शहरी गैस नेटवर्क के विस्तार और उर्वरक क्षेत्र की मांग में वृद्धि पर भी निर्भर है। 2030 तक, यह मांग 290 से 300 मिलियन वर्ग मीटर प्रतिदिन तक पहुंचने का अनुमान है।
भारत को खाड़ी देशों से जोड़ने वाली समुद्री पाइपलाइन की अवधारणा नई नहीं है। 1990 के दशक से इस प्रस्ताव के विभिन्न रूप समय-समय पर सामने आते रहे हैं, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता की जटिलता, वित्तपोषण की अनिश्चितता और अपर्याप्त राजनीतिक उत्साह के कारण वे ठंडे बस्ते में चले गए।
बहरहाल इसबार की पहल तीन कारणों से उत्साहवर्धक है। एक, समुद्र में पाइप बिछाने की तकनीक में काफी प्रगति हुई है। पर्याप्त भू-राजनीतिक झटकों की वजह से राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा हो गई है, और तीसरे, सरकारी संस्थाओं को काम के औपचारिक निर्देश मिले हैं। यह परियोजना अब केवल सैद्धांतिक मनोकामना नहीं है, बल्कि सक्रिय इंजीनियरिंग और डिप्लोमैटिक प्रयास है।
इस पाइपलाइन की संरचना से भारत को ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर से प्राकृतिक गैस प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। इन देशों के पास सामूहिक रूप से लगभग 2,500 ट्रिलियन घन फुट प्राकृतिक गैस का भंडार है। कतर के पास लगभग 868 ट्रिलियन घन फुट और ईरान के पास लगभग 1,649 ट्रिलियन घन फुट का भंडार है।
भारत की ऊर्जा सुरक्षा की तुलना चीन से करें, तो पाएंगे कि चीन ने अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ समय रहते उठा लिया है। भारत, जहां लगभग पूरी तरह से समुद्री पोतों से आने वाली एलएनजी पर निर्भर है, वहीं चीन ने व्यवस्थित रूप से भूमि और क्षेत्रीय पाइपलाइन गलियारों का एक नेटवर्क बना लिया है। इसके कारण वह होर्मुज़ पाइपलाइन के व्यवधान से काफी हद तक सुरक्षित हो गया है।
चीन की पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन, जो दिसंबर, 2019 से चालू है, पूरी क्षमता से रूस के साइबेरिया गैस क्षेत्रों से प्रति वर्ष 38 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) तक गैस की आपूर्ति करती है। उसकी दूसरी पाइपलाइन, पावर ऑफ साइबेरिया 2 है, जिसकी प्रस्तावित क्षमता 50 बीसीएम प्रति वर्ष है। वह मंगोलिया से होकर आएगी, पर अभी उसपर बातचीत चल रही है।
इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान से चीन का मध्य एशियाई पाइपलाइन नेटवर्क, तीन समानांतर लाइनों के माध्यम से 55 बीसीएम प्रति वर्ष गैस की ढुलाई करता है। चौथी लाइन निर्माणाधीन है जो कुल क्षमता को 85 बीसीएम प्रति वर्ष तक बढ़ा देगी।
भारत और चीन की भंडारण क्षमता में बड़ा अंतर है। भारत में 22 से 24 एलएनजी भंडारण टैंकों में लगभग 2 से 2.5 अरब घनमीटर गैस का भंडार है, जो राष्ट्रीय गैस खपत के 10 से 12 दिनों के बराबर है। वहीं, चीन 2026 के अंत तक लगभग 80 अरब घनमीटर भंडारण क्षमता हासिल करने की राह पर है , जो उसकी वार्षिक खपत का लगभग 20 प्रतिशत है।
अतीत में पाकिस्तान के रास्ते तुर्कमेनिस्तान और ईरान से पाइपलाइनें बिछाने की परियोजनाओं पर काम हुआ था, पर वे बन नहीं पाईं। भू-राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चुनौतियों के कारण दशकों से प्रस्तावित 1800 किलोमीटर लंबी तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान, पाकिस्तान-इंडिया (तापी) पाइपलाइन नहीं बन पाई। यह पाइपलाइन करीब 33 अरब घनमीटर गैस का परिवहन करती। दूसरी पाइपलाइन थी ईरान-पाकिस्तान-इंडिया (आईपीआई) लाइन। भारत ने भू-राजनीतिक कारणों और अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में खुद को इस परियोजना से लगभग अलग कर लिया।
भारत ने खनिज तेल का एक दीर्घकालीन भंडार ढांचा बना लिया है, पर गैस-भंडारण की विशाल अवसंरचना मौजूद नहीं है। अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और पश्चिम एशिया की लड़ाई के कारण, हमारी ऊर्जा सुरक्षा, जोखिम में पड़ गई है। यह पाइपलाइन आशा की एक किरण बन सकती है।

प्रेरणा

साड़ी में सजी भारतीय अस्मिता की वह अद्भुत खिलाड़ी

वर्ष 1924 का ओलंपिक खेल समारोह केवल खेल प्रतिभाओं का मंच नहीं था, बल्कि वह दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का भी एक विराट संगम बन चुका था। यूरोप और अमेरिका के खिलाड़ी आधुनिक परिधानों में अपनी चमक बिखेर रहे थे। टेनिस कोर्ट पर सफेद स्कर्ट, टोपी और पश्चिमी पहनावे का दबदबा था। ऐसे समय में जब मिश्रित युगल टेनिस प्रतियोगिता के लिए भारत की एक महिला खिलाड़ी कोर्ट पर उतरी, तो दर्शकों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह महिला किसी आधुनिक यूरोपीय पोशाक में नहीं, बल्कि पारंपरिक भारतीय साड़ी में थीं। दुनिया भर के दर्शक कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। वह खिलाड़ी थीं मेहरबाई टाटा, जो टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के बड़े पुत्र सर दोराबजी टाटा की पत्नी थीं।
उस दौर में जब भारत अभी अंग्रेजों का गुलाम था और भारतीय महिलाओं को सामाजिक बंधनों में जकड़कर देखा जाता था, तब मेहरबाई टाटा ने न केवल अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को गर्व के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत भी किया। साड़ी पहनकर टेनिस खेलना केवल एक फैशन या व्यक्तिगत पसंद नहीं थी, बल्कि यह भारतीय अस्मिता और आत्मविश्वास की एक सशक्त अभिव्यक्ति थी। उन्होंने यह संदेश दिया कि आधुनिकता अपनाने के लिए अपनी संस्कृति और पहचान को त्यागना आवश्यक नहीं है।
टेनिस जैसा तेज गति और फुर्ती वाला खेल साड़ी में खेलना आसान नहीं था। कोर्ट पर लगातार दौड़ना, तेज सर्विस को संभालना और हर दिशा में तेजी से प्रतिक्रिया देना किसी भी खिलाड़ी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन मेहरबाई टाटा ने अपनी अद्भुत चपलता, संतुलन और आत्मविश्वास से यह साबित कर दिया कि भारतीय नारी केवल परंपरा की प्रतीक ही नहीं, बल्कि सामर्थ्य और प्रतिभा की भी मिसाल है। विदेशी मीडिया ने उस समय उनके खेल और पहनावे दोनों की चर्चा की। अखबारों में उनकी तस्वीरें प्रकाशित हुईं और लोग हैरान थे कि एक महिला साड़ी पहनकर भी इतने प्रभावशाली ढंग से टेनिस खेल सकती है।
उन दिनों भारत में महिलाओं का खेलों में भाग लेना बहुत सीमित था। समाज की रूढ़िवादी सोच महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित रखने की कोशिश करती थी। खेल को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था और महिलाओं के लिए सार्वजनिक मंचों पर आना भी सहज स्वीकार्य नहीं था। ऐसे समय में मेहरबाई टाटा ने सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए खेल जगत में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने यह साबित किया कि प्रतिभा का संबंध लिंग या पहनावे से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मेहनत से होता है।
मेहरबाई टाटा केवल एक खिलाड़ी नहीं थीं, बल्कि सामाजिक चेतना और महिला सशक्तिकरण की अग्रदूत भी थीं। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। विशेष रूप से बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ उनकी आवाज बेहद प्रभावशाली रही। उस समय भारत में कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देना सामान्य बात मानी जाती थी, जिससे उनकी शिक्षा और स्वतंत्र जीवन की संभावनाएं समाप्त हो जाती थीं। मेहरबाई ने इस सोच को बदलने के लिए समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाई।
उनका व्यक्तित्व भारतीय आधुनिकता का एक अनूठा उदाहरण था। वे पश्चिमी शिक्षा और वैश्विक दृष्टिकोण से परिचित थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने यह दिखाया कि भारतीय परंपरा पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं, बल्कि गरिमा और आत्मसम्मान की पहचान है। साड़ी में टेनिस खेलना इसी आत्मगौरव का जीवंत प्रतीक बन गया।
आज जब खेलों में फैशन और ग्लैमर का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तब मेहरबाई टाटा की कहानी एक अलग प्रेरणा देती है। उन्होंने दुनिया को बताया कि किसी खिलाड़ी की असली पहचान उसके खेल, अनुशासन और आत्मविश्वास से होती है, न कि केवल उसके पहनावे से। भारतीय महिलाओं के लिए उनका जीवन संदेश देता है कि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए भी दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर सफलता प्राप्त कर सकती हैं। मेहरबाई टाटा की यह विरासत केवल खेल जगत तक सीमित नहीं है। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं के आत्मविश्वास को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय जब महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने के अवसर कम मिलते थे, उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कार्यों से यह साबित किया कि भारतीय नारी हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकती है।
उनकी कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी एक शताब्दी पहले थी। आधुनिक भारत में महिलाएं खेल, विज्ञान, राजनीति और व्यापार जैसे अनेक क्षेत्रों में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। लेकिन इस यात्रा की नींव उन साहसी महिलाओं ने रखी थी, जिन्होंने कठिन सामाजिक परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस दिखाया। मेहरबाई टाटा उन्हीं अग्रणी महिलाओं में शामिल थीं।
ओलंपिक के उस टेनिस कोर्ट पर साड़ी में खड़ी मेहरबाई केवल एक खिलाड़ी नहीं थीं, बल्कि वे भारत की संस्कृति, आत्मसम्मान और नारी शक्ति की जीवंत प्रतीक थीं। उन्होंने दुनिया को यह एहसास कराया कि भारतीयता किसी सीमा में बंधी हुई नहीं है। वह आधुनिकता के साथ कदम मिलाकर चल सकती है और फिर भी अपनी पहचान बनाए रख सकती है। यही कारण है कि उनका जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत है और आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देता है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी विश्व मंच पर सफलता हासिल की जा सकती है।

यह कैसा समाज है, जिसमें अदालतें समझाएं रिश्तों का धर्म

किसी भी सभ्यता की वास्तविक पहचान उसकी ऊँची इमारतों, चमकती सड़कों, आर्थिक प्रगति या तकनीकी उपलब्धियों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों, माता-पिता और निर्बल वर्ग के प्रति कितना संवेदनशील है। लेकिन आज का सबसे पीड़ादायक प्रश्न यही है कि जिस भारत ने "मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः" का उद्घोष किया, जिस धरती से "वसुधैव कुटुम्बकम्" का विचार पूरी दुनिया में पहुँचा, उसी भूमि पर आज माता-पिता को अपने ही घर में सम्मान और आश्रय पाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। हाल के वर्षों में देश की अदालतों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ी है, जहाँ वृद्ध माता-पिता को अपने ही बच्चों से संरक्षण, भरण-पोषण, रहने की व्यवस्था और संपत्ति पर अधिकार के लिए न्यायिक हस्तक्षेप लेना पड़ा। कहीं बेटे को अदालत यह निर्देश दे रही है कि वह अपनी वृद्ध मां को घर में एक कमरा, अलग स्नानघर और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए, तो कहीं दुर्व्यवहार करने वाली संतान को माता-पिता की संपत्ति से बेदखल करने के आदेश दिए जा रहे हैं। यह केवल कानूनी घटनाएँ नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक और नैतिक पतन की वे चेतावनियाँ हैं जो भविष्य के भारत की तस्वीर पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा रही हैं। वास्तव में यह अत्यंत विडंबनापूर्ण है कि जिस मां ने नौ महीने गर्भ में रखकर संतान को जीवन दिया, जिसने अपना रक्त, ममता और त्याग देकर उसे पाला, उसी मां को अपने ही घर में रहने के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़े। जिस पिता ने अपने पसीने और परिश्रम से घर बनाया, बच्चों का भविष्य संवारा, वृद्धावस्था में उसी घर में उसके अधिकार के लिए अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े, यह स्थिति केवल व्यक्तिगत कृतघ्नता नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनाओं के क्षरण का प्रमाण है। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भारत विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्थिक विकास, डिजिटल क्रांति, स्मार्ट शहर, वैश्विक नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की बातें हो रही हैं। लेकिन यदि घर के किसी कोने में बैठे वृद्ध माता-पिता अकेलेपन, उपेक्षा और अपमान का जीवन जी रहे हों, तो क्या यह विकास पूर्ण माना जा सकता है? यदि हमारे बुजुर्ग अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर और उपेक्षित हो जाएँ, तो हमारी सारी उपलब्धियाँ खोखली प्रतीत होती हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक निर्धनता की है। नई पीढ़ी का एक बड़ा वर्ग आत्मकेंद्रित होता जा रहा है। भौतिक उपलब्धियाँ, कैरियर, उपभोगवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणाएँ जीवन के केंद्र में आ गई हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों की ऊष्मा कम हो रही है और संवाद का स्थान डिजिटल माध्यम ले रहे हैं। परिणामतः बुजुर्गों का जीवन अकेलेपन, अवसाद और असुरक्षा का पर्याय बनता जा रहा है। यह सच है कि महानगरीय जीवन की अपनी कठिनाइयाँ हैं। रोजगार, समयाभाव, आर्थिक दबाव और बदलती जीवनशैली ने नई पीढ़ी की चुनौतियाँ बढ़ाई हैं। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद माता-पिता के प्रति दायित्व समाप्त नहीं हो सकते। भारतीय संस्कृति में माता-पिता की सेवा केवल सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन-मूल्य रही है। श्रवण कुमार का आदर्श केवल कथा नहीं, बल्कि भारतीय चेतना का हिस्सा है। दुर्भाग्य यह है कि आज संपत्ति और स्वार्थ ने अनेक संबंधों को प्रभावित किया है। अखबारों में आए दिन ऐसे समाचार दिखाई देते हैं जिनमें संपत्ति के लिए माता-पिता को प्रताड़ित किया जाता है, घर से निकाला जाता है, मानसिक यातना दी जाती है या उनकी उपेक्षा की जाती है। अनेक वृद्धाश्रम ऐसे माता-पिता से भरे पड़े हैं जिनकी सबसे बड़ी "गलती" केवल यह थी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए समर्पित कर दी। यदि यह प्रवृत्ति यूँ ही बढ़ती रही तो भारत भी उस दिशा में बढ़ सकता है जहाँ पश्चिमी देशों की तरह माता-पिता और संतान के संबंध केवल कानूनी और औपचारिक होकर रह जाएँ। पश्चिमी समाज में अनेक माता-पिता प्रारंभ से ही बच्चों को आत्मनिर्भर बना देते हैं क्योंकि वे भविष्य में उनसे देखभाल की अपेक्षा नहीं रखते। लेकिन भारतीय समाज का आधार इससे भिन्न रहा है। यहाँ परिवार केवल जैविक इकाई नहीं, बल्कि भावनात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था रहा है।
यह भी स्मरणीय है कि देश में वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 जैसे कानून बनाए गए हैं ताकि वृद्ध माता-पिता के अधिकारों की रक्षा हो सके। न्यायालयों ने अनेक अवसरों पर माता-पिता के संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित रखा है और दुर्व्यवहार करने वाली संतानों के विरुद्ध कठोर टिप्पणियाँ भी की हैं। लेकिन कानून केवल सुरक्षा दे सकता है, संवेदना नहीं। अदालतें कमरे दिला सकती हैं, सम्मान नहीं, भरण-पोषण का आदेश दे सकती हैं, लेकिन ममता और अपनत्व नहीं लौटा सकतीं। यही कारण है कि समाधान केवल कानूनी नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक होना चाहिए। परिवारों में संस्कारों की पुनर्स्थापना आवश्यक है। बच्चों को केवल उच्च शिक्षा और आधुनिक सुविधाएँ देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें मानवीय मूल्य भी देना होंगे। विद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को परिवार, सेवा, कृतज्ञता और बुजुर्ग सम्मान जैसे विषयों पर गंभीर पहल करनी चाहिए। आज आवश्यकता है कि विकसित भारत 2047 की अवधारणा में "वृद्ध सम्मान" को भी एक महत्वपूर्ण सूचक बनाया जाए। जिस देश में बुजुर्ग सुरक्षित, सम्मानित और संतुष्ट होंगे, वही वास्तव में विकसित कहा जा सकेगा। हमें ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जिनमें वृद्धजन कल्याण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और भावनात्मक सहयोग को प्राथमिकता मिले। साथ ही परिवारों को यह समझना होगा कि माता-पिता केवल जिम्मेदारी नहीं, हमारी जड़ें हैं। जिस वृक्ष की जड़ें सूख जाएँ, उसकी शाखाएँ अधिक समय तक हरी नहीं रह सकतीं। माता-पिता की उपेक्षा केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरी पीढ़ी की नैतिक पराजय है। यह भी विचारणीय है कि जो संतान आज अपने माता-पिता के साथ व्यवहार कर रही है, वही व्यवहार भविष्य में उसके हिस्से भी आ सकता है। बच्चे केवल उपदेश से नहीं, व्यवहार से सीखते हैं। यदि वे अपने माता-पिता को बुजुर्गों की उपेक्षा करते देखेंगे तो वही संस्कार आगे बढ़ेंगे।

अभियान

ज्येष्ठ पूर्णिमा की दिव्यता में छिपा आत्मशुद्धि, आस्था और प्रकाश का सनातन संदेश

सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि केवल समय का संकेत नहीं होती, बल्कि वह प्रकृति, ग्रहों, ऊर्जा और मानव जीवन के गहरे आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में चंद्रमा को मन, भावनाओं और चेतना का अधिपति कहा गया है और जब वही चंद्रमा अपनी संपूर्ण सोलह कलाओं के साथ आकाश में प्रकाशित होता है, तब पूर्णिमा का पावन अवसर आता है। हिन्दू पंचांग के अनुसार हर हिंदी महीने का समापन पूर्णिमा तिथि पर होता है और इस प्रकार वर्ष भर में बारह पूर्णिमाएं आती हैं। प्रत्येक पूर्णिमा का अपना अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा को विशेष रूप से अत्यंत पुण्यदायी और शुभ माना गया है। इस वर्ष यह पवित्र तिथि 30 मई, शनिवार को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पूर्णिमा अधिकमास या पुरुषोत्तम मास में आती है, तब उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है और इस दिन किए गए जप, तप, स्नान, दान और पूजा का अक्षय फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा की रात्रि केवल आकाशीय सौंदर्य का दृश्य नहीं होती, बल्कि यह मनुष्य के भीतर छिपे आध्यात्मिक प्रकाश को जागृत करने का अवसर भी मानी जाती है। भारतीय ऋषियों और मुनियों ने हजारों वर्षों पहले यह अनुभव किया था कि पूर्णिमा के दिन वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का विशेष संचार होता है। चंद्रमा की शीतल किरणें केवल प्रकृति को ही नहीं, बल्कि मनुष्य के मन और चेतना को भी प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि पूर्णिमा को ध्यान, साधना और मानसिक शांति का श्रेष्ठ समय माना गया है। सनातन परंपरा में यह विश्वास है कि इस दिन मन अधिक स्थिर और ग्रहणशील होता है तथा ईश्वर के प्रति भक्ति और साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।
ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि यह तिथि भगवान श्रीहरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और चंद्रदेव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। अधिकमास को स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय मास कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में किए गए पुण्य कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते और व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत रखने तथा पूजा-अर्चना करने से जीवन में मानसिक शांति, सकारात्मकता और सौभाग्य का वास होता है। भारतीय धार्मिक परंपराओं में ज्येष्ठ पूर्णिमा का संबंध भगवान शिव की अमरनाथ यात्रा से भी जुड़ा हुआ है। इसी दिन से श्रद्धालु गंगाजल लेकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। यह केवल यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, तपस्या और समर्पण का जीवंत प्रतीक है। कठिन पहाड़ी रास्तों और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं के चेहरे पर भक्ति का तेज दिखाई देता है। उनके हाथों में रखा गंगाजल भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह दृश्य भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक शक्ति और सामूहिक श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है।
धार्मिक ग्रंथों में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, अलकनंदा और शिप्रा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे आध्यात्मिक शुद्धि की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में जल को केवल जीवन का आधार नहीं, बल्कि पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है। जो लोग किसी कारणवश तीर्थस्थलों तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें घर पर स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए और स्नान करते समय पवित्र नदियों तथा तीर्थों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से भी पुण्यफल प्राप्त होता है।
ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व मनुष्य को बाहरी शुद्धता के साथ-साथ आंतरिक पवित्रता का भी संदेश देता है। इस दिन सात्विक जीवन शैली अपनाने का विशेष महत्व बताया गया है। क्रोध, ईर्ष्या, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी के प्रति दुर्भावना रखनी चाहिए। सनातन धर्म का मूल संदेश यही है कि मन, वचन और कर्म तीनों की शुद्धता ही सच्ची साधना है। इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहकर सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध बने रहें।
वट वृक्ष की पूजा का भी ज्येष्ठ पूर्णिमा पर विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में वट वृक्ष को अमरत्व, स्थिरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि और पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और सुनाने की परंपरा भी इस दिन विशेष रूप से निभाई जाती है। मान्यता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक सत्यनारायण कथा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।
सनातन धर्म में दान को अत्यंत श्रेष्ठ कर्म माना गया है और ज्येष्ठ पूर्णिमा पर इसका विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, फल तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। दान केवल वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि करुणा, सहानुभूति और मानवता की भावना का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सच्चे मन से किया गया दान पितरों को शांति प्रदान करता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और विनम्रता के साथ योग्य व्यक्ति को दान देने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति तक हो सकती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सूर्य पूजा का भी विशेष महत्व है। प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करते हुए 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। सूर्यदेव को जीवन, प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य और नकारात्मकता दूर होती है तथा आत्मबल और सकारात्मकता का विकास होता है। सूर्य की उपासना मनुष्य को कर्म, अनुशासन और निरंतरता का संदेश देती है।
रात्रि के समय चंद्रदेव की पूजा का भी विशेष विधान बताया गया है। चंद्रमा को मानसिक शांति, शीतलता और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा के साथ आकाश में प्रकाशित होता है, तब उसकी चांदनी वातावरण में अद्भुत शांति का अनुभव कराती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस रात चंद्रदेव को अर्घ्य देने से मानसिक तनाव और चिंता दूर होती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष होता है या जो मानसिक अस्थिरता, भय और तनाव से पीड़ित रहते हैं, उनके लिए चंद्र पूजा अत्यंत लाभकारी मानी गई है।
इस पावन अवसर पर चंद्रमा की ओर मुख करके आसन पर बैठकर मंत्र जाप करने की परंपरा भी है। ऐसा माना जाता है कि चंद्र मंत्रों का जाप करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति को आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। पूर्णिमा की उजली चांदनी मनुष्य को यह संदेश देती है कि जैसे चंद्रमा अंधकार को दूर करके पूरी सृष्टि को प्रकाशित करता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर ज्ञान, करुणा और सत्य का दीप जलाना चाहिए।
ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा वास्तव में आत्मशुद्धि, सेवा, संयम और आध्यात्मिक जागरण का महापर्व है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलन, सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देने वाला अवसर है। सनातन धर्म की यही विशेषता है कि वह प्रकृति, ग्रहों, ऋतुओं और मानव चेतना को एक सूत्र में जोड़कर जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करता है। पूर्णिमा की यह दिव्य रात्रि मनुष्य को यह एहसास कराती है कि वास्तविक प्रकाश बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर मौजूद है और जब वह ईश्वर, प्रकृति और आत्मा के साथ जुड़ता है, तभी जीवन में सच्चे सुख, शांति और संतुलन का उदय होता है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

पिता की कैंसर से मौत के बाद कल्पेश पटेल ने रासायनिक खाद छोड़ चुनी प्राकृतिक खेती की राह : आज देश में एक 'रोल मॉडल' के रूप में उभरे

- सूरत जिले की ओलपाड तहसील के सरस गांव निवासी कल्पेश पटेल ने पिता की मौत के बाद 2019 से शुरू की प्राकृतिक खेती
- कल्पेश 50 से अधिक किस्मों के केलों की खेती करते हैं, देश भर से किसान और कृषि वैज्ञानिक उनकी केले की खेती को देखने के लिए सरस गांव आते हैं
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों से रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने और रासायनिक खाद के विकल्प के तौर पर जैविक खाद अपनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की है

गांधीनगर : कभी-कभी किसी संवेदनशील व्यक्ति के जीवन में घटित कोई घटना उसके पूरे जीवन को बदल देती है और फिर वह कुछ ऐसा करता है, जो दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन जाता है। सूरत जिले की ओलपाड तहसील के सरस गांव के किसान कल्पेश पटेल के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कल्पेश पटेल सूरत स्थित फैक्ट्री में केमिकल ऑपरेटर के रूप में नौकरी करते हैं। उनके पिता रमणभाई पटेल की कैंसर से मौत होने के बाद कल्पेश पटेल के जीवन में एक नया मोड़ आया। पिता की कैंसर से मौत के बाद उन्होंने तय किया कि वह अपने खेत में अब कभी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहरीले कीटनाशकों को छोड़कर कल्पेश पटेल ने प्राकृतिक खेती अपना ली।

स्वभाव से प्रकृति प्रेमी कल्पेश पटेल ने 2019 से प्राकृतिक खेती का राह चुनी। उन्होंने गुजरात सरकार के कृषि विभाग की ओर से दी जाने वाली प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत बनाना सीखा। इस प्रकार उन्होंने जीवन में एक नई शुरूआत की।

केले की विभिन्न किस्मों की खेती और उत्पादन में बनें रोल मॉडल

कल्पेश पटेल को विरासत में करीब आठ बीघा जमीन मिली है। उन्होंने साढ़े तीन बीघा जमीन पर केले की 50 से अधिक किस्में उगाई हैं, जिनमें पूवन, आधापुरी, रस्थली, लाल केळ, ब्लू जावा, बरराई, महालक्ष्मी और इलायची केला आदि शामिल हैं।

केले की विभिन्न किस्मों के साथ-साथ उन्होंने उत्पादन में भी रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2025 में उनके खेत में केले के एक गुच्छे का वजन 73 किलो था। आम तौर पर केले के एक गुच्छे का वजन 20 से 30 किलो के आसपास होता है। लेकिन, कल्पेश पटेल की बाड़ी में केले के गुच्छे का औसत वजन 30 किलो से अधिक होता है।

जीवन का मोड़ और नए प्रयोग

कल्पेश पटेल ने प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ने की वजह का खुलासा करते हुए कहा, "जब मेरे पिताजी को कैंसर हुआ, तभी मेरे मन में यह विचार आया कि अब रासायनिक खाद के जहर से मुक्त होना पड़ेगा और धरती माता को भी इस जहर से मुक्त करना है। प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ना होगा। जब पिताजी खेती करते थे, तब वे खेत में बहुत अधिक कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते थे और उनके पूरे शरीर से उस दवा की दुर्गंध आती थी। चूंकि मैं खेती से जुड़ा नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ कहता भी नहीं था। लेकिन, जब उन्हें कैंसर हुआ और बाद में उनका निधन हुआ, तो इससे मेरे जीवन में एक नया मोड़ आ गया।"

प्राकृतिक खेती के फायदे बताते हुए कल्पेश पटेल ने कहा, "मैं पिछले सात वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूं। मैंने 'जंगल मॉडल' भी अपनाया है। मैं अपने खेत उत्पादों में वैल्यू एडिशन करता हूं और 'मेरा माल, मेरा भाव' के सिद्धांत से खेती और उपज की बिक्री करता हूं। प्राकृतिक खेती के कारण प्रति बीघा जमीन पर होने वाला 15 से 20 हजार रुपए का रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का खर्च बंद हो गया है। यही नहीं, मिट्टी की सेहत सुधरने से केले का बंपर उत्पादन होने लगा है। सालाना साढ़े तीन बीघा के खेत में केले की खेती से 10 से 12 लाख रुपए की आय होती है।"

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों से रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने और रासायनिक खाद के विकल्प के तौर पर जैविक खाद अपनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य में प्राकृतिक खेती को एक नई रफ्तार मिली है। किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता दी जाती है। राज्य के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत भी गांव-गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक कृषि की दिशा में मोड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

वैल्यू एडिशन कर बढ़ाई खेती की आय

गुजरात सरकार ने प्राकृतिक खेत उत्पादों की बिक्री के लिए एक प्रयोग शुरू किया है। गुजरात के विभिन्न शहरों में प्राकृतिक कृषि बाजार बनाए हैं, जहां प्राकृतिक खेती करने वाले किसान अपने उत्पाद बेच सकते हैं। कल्पेश पटेल सूरत के वेसू स्थित कृषि बाजार में केला और अन्य उत्पाद बेचते हैं। इतना ही नहीं, यदि कच्चे केले नहीं बिक पाते, तो कल्पेश उन केलों से वेफर और पाउडर जैसे उत्पाद बनाते हैं, जिससे वैल्यू एडिशन के जरिए उनकी आय बढ़ जाती है।

घर बैठे बेचते हैं देश भर में केले

कल्पेश पटेल का केले की प्राकृतिक खेती का संदेश देश भर में पहुंच गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके साथ वार्तालाप किया और कल्पेश पटेल की सफलता की कहानी को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। कल्पेश को दूसरे राज्यों से भी ऑर्डर मिलते हैं, जिसे वे पार्सल के जरिए संबंधित राज्य में भेजते हैं।

नेताओं की पेंशन बंद करो, जन कल्याण के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करो: छगनलाल मेवाड़ा की मांग

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश में आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी, कारोबार में मंदी, शिक्षा का निजीकरण, कॉरपोरेट कंपनियों जैसे महंगे निजी अस्पताल, रामभरोसे जैसे सरकारी अस्पताल और स्कूल - इन दिनों सरकार में बैठे पार्षदों से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक, हर कोई जनता की सेवा की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें, तो इन मंत्रियों और नेताओं का मुख्य उद्देश्य सत्ता की कुर्सी पर बैठना और उसका स्वाद चखना है। चूंकि उन्हें बंगले, दफ्तर, गाड़ियां, बिजली, टेलीफोन, नौकर, पेट्रोल, रेल और हवाई यात्रा जैसी सभी जरूरी सुविधाएं अपने परिवार के साथ मुफ्त में मिलती हैं, इसलिए वे सत्ता नहीं छोड़ते। जनता की सेवा करना उनके लिए एक बहाना है। यह सब इसलिए चल रहा है क्योंकि जनता ही उन्हें अपने कंधों पर बिठा रही है।

अब बुनियादी बातों पर आते हैं। नेताओं को दी जाने वाली ये पेंशन बंद कर देनी चाहिए क्योंकि चुनाव लड़कर और सत्ता का आनंद लेकर अमीर बने ये आधुनिक अंग्रेज उनके माता-पिता जैसे नहीं हैं। करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों के बंगले, लाखों की महंगी गाड़ियां आदि होने के बावजूद, जब वे सेवानिवृत्त होते हैं (चाहे दो कार्यकाल हारने के बाद या चुनाव जीतकर करोड़ों कमाने और स्वेच्छा से राजनीति छोड़ने के बाद), तो उन्हें भारी पेंशन मिलती है। महंगाई के कारण यह जनता के लिए एक बड़ा झटका है। वे जनता के करों से पेंशन वापस भी लेते हैं। इस प्रकार, सत्ता में रहने और सत्ता छोड़ने के बाद भी, उनकी पेंशन एक तरह का आराम बनी रहती है। इन सभी सुविधाओं को बंद कर देना चाहिए।

यहाँ मुद्दा यह है कि इन प्रभावशाली लोगों की पेंशन बंद कर देनी चाहिए। यह पेंशन सरकारी बजट का एक बड़ा हिस्सा है। अगर नेताओं की पेंशन बंद कर दी जाए, तो हर साल करोड़ों रुपये बचाए जा सकते हैं। सरकार इस बची हुई रकम को अन्य क्षेत्रों में निवेश कर जन कल्याणकारी कार्यों में लगा सकती है। जैसे सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध कराना, सरकारी स्कूल बनवाना, अच्छी सड़कें और पुल बनवाना आदि। पेंशन से बची हुई रकम का इस्तेमाल इन कार्यों में किया जा सकता है।

और अंत में, सत्ता में मौजूद सभी दलों के नेता, चाहे वे सत्ता में हों या विपक्ष में, सरकारी पेंशन के लाभ छोड़ने को तैयार नहीं हैं। क्योंकि सभी नेता केवल जनता की सेवा करने की बात करते हैं। जब देश के हित में कुछ त्यागने की बात आती है, तो वे सब चुप हो जाते हैं। यानी, हर कोई सरकारी भेस में नागा है।

चाहे बीते दौर के नेता हों या सेवा करने के इच्छुक नए युवा, वर्तमान नेताओं में से एक ऐसा नेता है जो उनके लिए आदर्श बन सकता है। वह नेता जो देश के हित में बिना पेंशन लिए जीवन भर जनता की सेवा करने का संकल्प लेता है और जनता के धन को महत्व देते हुए सरकारी सुविधाओं से दूर रहने की सार्वजनिक घोषणा करता है, वह किसी भी पार्टी का क्यों न हो? जनता की सेवा के नाम पर नेता मौज-मस्ती करते हैं और करोड़ों रुपये के लिए खेलते हैं। इससे जनता का धन जनता के हित में उपयोग होने से रुक जाएगा।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि यदि 1 अप्रैल, 2004 के बाद 35-38 वर्षों तक सरकारी सेवा में रहे लोगों की पेंशन रोकी जा रही है, जिससे उनके पिछले जीवन की आय का आधार छीन लिया गया है और उन्हें पेंशनभोगी बना दिया गया है, तो पांच वर्षों तक चुनाव जीतने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले और पेंशन प्राप्त करने वाले नेताओं की पेंशन भी रोक दी जानी चाहिए।

इस संबंध में, विकास उपभोक्ता संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के दक्षिण गुजरात अध्यक्ष, छगनलाल दौलतराम मेवाड़ा, जनहित में नेताओं की पेंशन रोकने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को एक लिखित पत्र सौंपेंगे और पेंशन रोकने तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर करेंगे।

पश्चिम रेलवे द्वारा मानसून 2026 की व्यापक तैयारी,मुंबई की लाइफलाइन उन्नत मानसून तैयारी उपायों के साथ पूरी तरह मुस्तैद

पश्चिम रेलवे द्वारा आगामी मानसून सीजन के दौरान सुरक्षित एवं निर्बाध ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में व्यापक मानसून तैयारी कार्य किए गए हैं। इन समग्र उपायों का उद्देश्य भारी वर्षा के दौरान व्यवधानों को न्यूनतम करना तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उल्लेखनीय है कि मानसून तैयारी एवं शमन के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा की गई पहलों के परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में किसी भी स्थान पर लंबे समय तक जलभराव अथवा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई तथा मानसून के कारण कोई बड़ी सेवा बाधा नहीं आई।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आगामी मानसून सीजन के दौरान निर्बाध ट्रेन सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु मिशन मोड पर कई लक्षित कार्य किए गए हैं। पुलियों, नालों एवं जल निकासी मार्गों की सफाई और गाद निकासी, रेलवे पटरियों के किनारे जमा मलबा एवं कचरा हटाना, नई जल निकासी प्रणालियों के निर्माण, अतिरिक्त जल निकासी पंपों की स्थापना तथा पेड़ों की छंटाई जैसी प्रमुख गतिविधियाँ व्यापक स्तर पर की गई हैं।

पश्चिम रेलवे ने मानसून परिचालन के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है, जिसमें निवारक उपाय, आकस्मिक योजना तथा तकनीकी हस्तक्षेप शामिल हैं, ताकि व्यवधानों को न्यूनतम किया जा सके और रेलवे अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

श्री विनीत ने पश्चिम रेलवे द्वारा उठाए गए निम्नलिखित प्रमुख कदमों के बारे में विस्तार से बताया:

व्यापक जल निकासी कार्य: कुल 58 पुलियों एवं पुल जलमार्गों की सफाई का कार्य चिन्हित किया गया है, जिनमें से 90% कार्य पूरा किया जा चुका है। इसी प्रकार लगभग 60 किलोमीटर नालों की गाद निकासी एवं सफाई का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 50 किलोमीटर से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त, संवेदनशील स्थानों पर जल निकासी की सुगमता हेतु नए नाले एवं मैनहोल बनाए गए हैं।

बाढ़ नियंत्रण उपाय: उपनगरीय खंड के संवेदनशील स्थानों पर कुल 126 उच्च क्षमता वाले जल निकासी पंप लगाए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक हैं। आपातकालीन उपयोग हेतु अतिरिक्त पंप भी रखरखाव डिपो में रणनीतिक रूप से उपलब्ध कराए गए हैं।

बाढ़ एवं वर्षा निगरानी: वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करने हेतु 40 बाढ़ मापक यंत्र तथा 6 ऑटोमेटेड डिजिटल रेन गेज (ARG) रणनीतिक स्थानों पर लगाए गए हैं, जो वर्षा एवं जलस्तर की सटीक जानकारी प्रदान करते हैं।

उन्नत जलस्तर निगरानी: संवेदनशील पुलों पर वास्तविक समय एवं प्रमाणिक जलस्तर जानकारी प्राप्त करने हेतु पश्चिम रेलवे ने मुंबई उपनगरीय खंड के महत्वपूर्ण स्थानों पर SCADA-आधारित जलस्तर निगरानी उपकरण स्थापित किए हैं, जो सतत निगरानी एवं समय पर चेतावनी सुनिश्चित करते हैं।

मलबा सफाई अभियान: पिछले मानसून से अब तक उपनगरीय खंड से मलबा, कचरा एवं निकाली गई मिट्टी हटाने हेतु मलबा विशेष ट्रेनों के लगभग 480 फेरे संचालित किए गए हैं। यह कार्य मलबा विशेष वैगनों, जेसीबी, पोकलेन मशीनों तथा श्रमिकों की सहायता से किया जा रहा है। इससे मानसून के दौरान वर्षा जल की सुचारू निकासी सुनिश्चित होती है।

आधुनिक तकनीक का उपयोग: पुलियों एवं नालों की सफाई के सर्वेक्षण एवं निगरानी हेतु ड्रोन तथा फ्लोटर कैमरा ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। चिन्हित स्थानों पर गहन सफाई के लिए विशेष सक्शन एवं डी-स्लजिंग मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है।

माइक्रो-टनलिंग एवं अतिरिक्त जल निकासी: वर्षा जल निकासी क्षमता बढ़ाने के लिए 1200 मिमी एवं 1800 मिमी व्यास की पाइपों द्वारा माइक्रो-टनलिंग कार्य किए जा रहे हैं। चर्चगेट-विरार खंड के बीच माइक्रो-टनल पाइप ओपनिंग्स की संख्या बढ़कर 19 हो गई है, जिससे जल निकासी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ट्रैक संरक्षा एवं संवेदनशील स्थान प्रबंधन: उपनगरीय खंड के बाढ़ संभावित एवं संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहाँ ट्रैक ऊँचाई बढ़ाने एवं अतिरिक्त जल निकासी व्यवस्था जैसे स्थान-विशिष्ट सुधारात्मक कार्य किए गए हैं।

वृक्ष प्रबंधन: तेज हवा एवं बारिश के दौरान सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने तथा ट्रैक पर अवरोध से बचने के लिए पटरियों के समीप स्थित पेड़ों की छंटाई एवं हटाने का कार्य किया जा रहा है।

100 वर्ष पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त रेलकर्मी श्री उमेदभाई पटेल का वडोदरा मंडल द्वारा गरिमामय सम्मान

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा आज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, प्रतापनगर में एक भावपूर्ण एवं गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री उमेदभाई बेचरभाई पटेल के शतायु जीवन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, श्री उमेदभाई बेचरभाई पटेल वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक कार्यालय, वडोदरा में अकाउंट असिस्टेंट पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अपने सेवाकाल में उन्होंने निष्ठा, ईमानदारी एवं कर्तव्यपरायणता के साथ रेलवे सेवा को समर्पित किया। उनके जीवन के 100 वर्ष पूर्ण होना न केवल उनके परिवार बल्कि रेलवे परिवार के लिए भी गर्व एवं प्रेरणा का विषय है।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक, वडोदरा श्री राजू भडके ने श्री पटेल को पुष्पगुच्छ, शॉल एवं प्रशस्ति-पत्र भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय एवं दीर्घायु जीवन की मंगलकामनाएँ व्यक्त कीं। समारोह के दौरान वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक श्री आर्य किर्णेन्दु ने भी श्री पटेल का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया तथा उनके स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन की कामना की।

अपने संबोधन में श्री पटेल ने रेलवे सेवा के दौरान के अनेक प्रेरणादायक अनुभव एवं संस्मरण साझा किए। उन्होंने अपने कार्यकाल की स्मृतियों को उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बाँटते हुए अनुशासन, समर्पण एवं सकारात्मक जीवनशैली के महत्व पर प्रकाश डाला।

समारोह का वातावरण अत्यंत आत्मीय एवं प्रेरणादायी रहा। उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्री पटेल के स्वस्थ, सक्रिय एवं सम्मानपूर्ण जीवन को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया।

इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक, वडोदरा श्री नीरज धमीजा, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री अविनाश कुमार सहित लेखा विभाग, वडोदरा के अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

वडोदरा मंडल में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक एवं मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री राजू भडके की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन दिनाँक 25 मई, 2026 को किया गया। इस अवसर पर हिंदी साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत जयंती भी मनाई गयी एवं राजभाषा प्रश्न-मंच का भी आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने अपने कर कमलों से हिंदी साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया। इसके उपरांत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महोदय द्वारा मूल हिंदी टिप्पण आलेखन पुरस्कार योजना 2024-25 के विजेता कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

अपने संबोधन में मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने कहा कि सरकारी कार्यों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग हमारा संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने सभी शाखा अधिकारियों से सरल हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को पत्राचार एवं ई-ऑफिस में हिंदी नोटिंग प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार से प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं। अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री नीरज धमीजा ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सरकारी कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल देते हुए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हिंदी में पत्राचार, नोटिंग तथा फाइलों एवं रजिस्टरों में द्विभाषी शीर्षकों का उपयोग सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी कार्यालयों में हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रबड़ मोहरों एवं नाम पट्टों के प्रयोग के निर्देश भी दिए। श्री नवीन यादव, प्रभारी अधिकारी (राजभाषा) एवं मंडल संरक्षा अधिकारी द्वारा दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही की हिंदी प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत की गई तथा वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 पर चर्चा की गई। उन्होंने हिंदी साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन एवं हिंदी साहित्य में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए भारतीय रेल विषयक राजभाषा प्रश्न-मंच का संचालन भी किया। प्रश्न-मंच के विजेताओं को स्मृति-चिह्न प्रदान किए गए।

कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ अनुवादक श्री गुरु प्रसाद जोशी द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सहित मंडल के वरिष्ठ शाखा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सोना वायदा में 1292 रुपये और चांदी वायदा में 5618 रुपये की गिरावट: क्रूड ऑयल वायदा में 269 रुपये की वृद्धि

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 516719.54 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 29179.66 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 487539.88 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2624.51 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 18747.33 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 158789 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 158789 रुपये और नीचे में 157735 रुपये पर पहुंचकर, 159081 रुपये के पिछले बंद के सामने 1292 रुपये या 0.81 फीसदी घटकर 157789 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी मई वायदा 922 रुपये या 0.72 फीसदी लुढ़ककर 126524 रुपये प्रति 8 ग्राम बोला गया। गोल्ड-पेटल मई वायदा 152 रुपये या 0.95 फीसदी लुढ़ककर 15789 रुपये प्रति 1 ग्राम बोला गया। सोना-मिनी जून वायदा सत्र के आरंभ में 158120 रुपये के भाव पर खूलकर, 158150 रुपये के दिन के उच्च और 157225 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1196 रुपये या 0.75 फीसदी लुढ़ककर 157319 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 158299 रुपये के भाव पर खूलकर, 158299 रुपये के दिन के उच्च और 157244 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 158506 रुपये के पिछले बंद के सामने 1103 रुपये या 0.7 फीसदी लुढ़ककर 157403 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा 274727 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 274727 रुपये और नीचे में 269913 रुपये पर पहुंचकर, 276716 रुपये के पिछले बंद के सामने 5618 रुपये या 2.03 फीसदी गिरकर 271098 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 5356 रुपये या 1.91 फीसदी गिरकर 275058 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 5291 रुपये या 1.89 फीसदी की गिरावट के साथ 275080 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

मेटल वर्ग में 4514.74 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 6.55 रुपये या 0.49 फीसदी गिरकर 1341 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता मई वायदा 30 पैसे या 0.08 फीसदी की नरमी के साथ 374.35 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 75 पैसे या 0.19 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 387.4 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 1.05 रुपये या 0.52 फीसदी की मजबूती के साथ 204.4 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कमोडिटी वायदाओं में 29179.66 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 487539.88 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 18747.33 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5830.86 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जून वायदा 8778 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 8980 रुपये और नीचे में 8749 रुपये पर पहुंचकर, 269 रुपये या 3.12 फीसदी बढ़कर 8895 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जून वायदा 268 रुपये या 3.11 फीसदी की मजबूती के साथ 8895 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा 279.9 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 283.5 रुपये और नीचे में 278.4 रुपये पर पहुंचकर, 277.5 रुपये के पिछले बंद के सामने 2.5 रुपये या 0.9 फीसदी की तेजी के संग 280 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 2.2 रुपये या 0.79 फीसदी की तेजी के संग 279.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा 959 रुपये पर खूलकर, 90 पैसे या 0.09 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 955.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 10339.89 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 8407.44 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3057.33 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 782.85 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 27.03 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 637.76 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन सिंों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 3909.30 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1903.46 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 5.45 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9772 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 65406 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 20001 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 324185 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 49673 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 10192 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 25722 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 84206 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 15383 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 23186 लोट के स्तर पर था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जून 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 44.3 रुपये की बढ़त के साथ 277.9 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जून 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.45 रुपये की बढ़त के साथ 14.55 रुपये हुआ। सोना मई 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 410 रुपये की गिरावट के साथ 162.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 275000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3174 रुपये की गिरावट के साथ 331 रुपये हुआ। तांबा जून 1450 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.74 रुपये की गिरावट के साथ 8.3 रुपये हुआ। जस्ता जून 370 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.83 रुपये की गिरावट के साथ 6.5 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जून 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 85.3 रुपये की गिरावट के साथ 246.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जून 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.7 रुपये की गिरावट के साथ 14.2 रुपये हुआ।

सोना मई 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 44 रुपये की बढ़त के साथ 146 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 265000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 80.5 रुपये की बढ़त के साथ 217.5 रुपये हुआ। तांबा जून 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.34 रुपये की बढ़त के साथ 10.42 रुपये हुआ। जस्ता जून 370 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.17 रुपये की गिरावट के साथ 6.16 रुपये हुआ।

गुजरात की चीनी सहकारी समितियों तथा गन्ना किसानों के हित में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

▶▶ राज्य सरकार ने वर्ष 2007-08 से 2014-15 के दौरान चीनी समितियों द्वारा किसानों को चुकाई गई गन्ने की कीमतों को दी आधिकारिक मंजूरी : सहकारिता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

▶▶ इस निर्णय से सहकारी चीनी समितियों पर 1599 करोड़ रुपए का बोझ कम होगा, दो लाख से अधिक गन्ना किसानों और सहकारी समितियों को मिलेगी बड़ी राहत

▶▶ मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने चीनी सहकारी समितियों और किसानों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी , केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का आभार व्यक्त किया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सहकारी क्षेत्र, विशेषकर गन्ना किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। इस निर्णय की जानकारी देते हुए कृषि एवं सहकारिता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2007-08 से 2014-15 के दौरान चीनी समितियों द्वारा गन्ना किसानों को चुकाई गई कीमतों को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से गुजरात की चीनी सहकारी समितियों को लगभग 1500 करोड़ रुपए का बड़ा आर्थिक लाभ होगा, जिससे दो लाख से अधिक किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

इस निर्णय की पृष्ठभूमि में मंत्री श्री वाघाणी ने कहा कि देश की चीनी समितियां आम तौर पर गन्ने की खेती करने वाले किसानों को भारत सरकार द्वारा तय किए गए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के हिसाब से कीमतों का भुगतान करती हैं। गुजरात की सहकारी चीनी समितियों ने केवल चीनी ही नहीं, बल्कि मोलासिस, इथेनॉल और को-जनरेशन द्वारा बिजली उत्पादन जैसे बाय-प्रोडक्ट से प्राप्त होने वाली आय का अधिकतम लाभ भी किसानों तक पहुंचाया है। इसके परिणामस्वरूप, गुजरात के गन्ना उत्पादक किसानों को देश के अन्य राज्यों की तुलना में हमेशा अधिक कीमतें मिली हैं।

सहकारिता मंत्री ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि अतीत में आयकर विभाग ने एफआरपी से अधिक कीमतों को मुनाफा मानते हुए गुजरात की विभिन्न चीनी सहकारी समितियों को टैक्स की डिमांड नोटिस भेजी थी। वर्ष 2007-08 से 2014-15 की अवधि से संबंधित इस जटिल मुद्दे के कारण राज्य की चीनी सहकारी समितियों पर लगभग 1500 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ने की स्थिति पैदा हो गई थी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करने के बाद केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के प्रयासों से वर्ष 2023 में आयकर कानून के प्रावधानों में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इन सुधारों के अनुसार, आयकर के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई गन्ने की कीमतों को मान्यता देने का कानूनी प्रावधान किया गया।

श्री पटेल ने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए इस सुधार की रोशनी में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य स्तर पर सिफारिशें करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात सरकार ने चीनी सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2007-08 से 2014-15 के दौरान किसानों को चुकाई गई गन्ने की कीमतों को आधिकारिक स्वीकृति देने का क्रांतिकारी किसान हितैषी निर्णय किया है।

इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री और मुख्यमंत्री का चीनी सहकारी समितियों और किसानों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए श्री वाघाणी ने यह साफ किया कि राज्य सरकार सहकारी क्षेत्र और किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। वर्तमान में राज्य की चीनी सहकारी समितियां दो लाख से अधिक गन्ना उत्पादक किसानों को सीधे भुगतान करके किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में अहम योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय सहकारी क्षेत्र के आधार को और भी मजबूत और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

मई - 2026 का मुख्यमंत्री का ऑनलाइन स्वागत जन शिकायत निवारण कार्यक्रम 29 मई शुक्रवार को आयोजित होगा

▶▶ गुरुवार 28 मई की सार्वजनिक छुट्टी के कारण राज्य स्वागत कार्यक्रम में बदलाव किया गया

गांधीनगर : राज्य के नागरिकों की समस्याएं तथा प्रस्तुतियों के त्वरित निवारण का प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित किया जाने वाला मुख्यमंत्री का राज्य स्वागत ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम इस बार 29 मई, शुक्रवार के दिन आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार ने गुरुवार 28 मई को घोषित की गई बकरी ईद की सार्वजनिक छुट्टी के अनुसंधान में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का मई-2026 का राज्य स्वागत गुरुवार के बजाय 29 मई को आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है।

इस राज्य स्वागत कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता 29 मई शुक्रवार को सुबह 8 से 11 बजे तक अपनी समस्या मुख्यमंत्री के जनसंपर्क इकाई स्वर्णिम संकुल-2 गांधीनगर में प्रत्यक्ष उपस्थित रहकर दे सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल शुक्रवार को 29 मई को दोपहर के बाद राज्य स्वागत कार्यक्रम में प्रत्यक्ष उपस्थित रहकर नागरिकों के प्रस्तुतियां सुनेंगे तथा प्रस्तुतियों के निवारण-समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को मार्गदर्शन देंगे।

उमरेठ मत क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक श्री हर्षदभाई परमार ने विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी के समक्ष विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों की विशेष उपस्थिति

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की विशेष उपस्थिति में गुजरात विधानसभा की उमरेठ सीट पर हाल ही में आयोजित उप चुनाव में नवनिर्वाचित विधायक श्री हर्षदभाई गोविंदभाई परमार ने मंगलवार को गांधीनगर में विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी के समक्ष विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इस शपथ विधि समारोह में विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री बालकृष्ण शुक्ल, वैधानिक एवं संसदीय मामलों के मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य तथा विधायक उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे द्वारा मुंबई सेंट्रल–काठगोदाम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में किया गया नियमित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा मुंबई सेंट्रल और काठगोदाम के बीच नियमित रेल संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ट्रेन संख्या 09075/09076 मुंबई सेंट्रल – काठगोदाम – मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को नियमित किया गया है। यह नियमित सेवा संशोधित ट्रेन संख्या 21907/21908 मुंबई सेंट्रल – काठगोदाम – मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में परिचालित की जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 21907 मुंबई सेंट्रल – काठगोदाम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस की नियमित सेवा 27 मई, 2026 से मुंबई सेंट्रल से प्रारंभ होगी, जबकि ट्रेन संख्या 21908 काठगोदाम – मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस की नियमित सेवा 28 मई, 2026 से काठगोदाम से प्रारंभ होगी।

ट्रेन संख्या 21907 मुंबई सेंट्रल – काठगोदाम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार को मुंबई सेंट्रल से 10:55 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 13:50 बजे काठगोदाम पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 21908 काठगोदाम – मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रत्येक गुरुवार को काठगोदाम से 17:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 21:00 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, शामगढ़, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, बदायूं, बरेली जं., बरेली सिटी, इज्जतनगर, बहेड़ी, किच्छा, लालकुआं तथा हल्द्वानी स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, शयनयान तथा द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे होंगे।

ट्रेन संख्या 09075/09076 मुंबई सेंट्रल – काठगोदाम – मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल में आरक्षण कराने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि संशोधित ट्रेन संख्याओं को ध्यान में रखें, क्योंकि यह ट्रेन उपर्युक्त तिथियों से ट्रेन संख्या 21907/21908 के रूप में परिचालित की जाएगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं रेक संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

जूनागढ़ शहर को मिलेगी बड़ी राहतः रेलवे बोर्ड ने ग्रोफेड में नए मीटर गेज स्टेशन को दी स्वीकृति; समपार फाटकों पर रोज़ाना के जाम से मिलेगी मुक्ति

जूनागढ़ शहर के नागरिकों को लंबे समय से चली आ रही यातायात समस्या से बड़ी राहत मिलने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल अंतर्गत विसावदर–जूनागढ़ मीटर गेज खंड पर ग्रोफेड क्षेत्र में नए मीटर गेज स्टेशन के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है।

शहर के बीच की मीटर गेज लाइन होगी स्थायी रूप से बंद

इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ग्रोफेड स्टेशन चालू होने के बाद ग्रोफेड और वर्तमान जूनागढ़ स्टेशन के बीच लगभग 4.2 किलोमीटर लंबा मीटर गेज रेलखंड स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। यह रेलखंड वर्तमान में शहर के घनी आबादी वाले हिस्से से होकर गुजरता है और इसके कारण 7 समपार फाटक लंबे समय तक बंद रहते हैं, जिससे पूरे शहर में गंभीर यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद शहर के भीतर स्थित सभी 7 समपार फाटक समाप्त हो जाएंगे, जिससे जूनागढ़ शहर को लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक समस्या से स्थायी राहत मिलेगी।

नागरिकों को होने वाले प्रमुख लाभ

ट्रैफिक जाम से मुक्ति

मीटर गेज लाइन बंद होने के साथ शहर के भीतर स्थित सभी 7 समपार फाटक समाप्त हो जाएंगे। इससे नागरिकों, स्कूली बच्चों, कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों तथा आपातकालीन सेवाओं को बार-बार होने वाले जाम से राहत मिलेगी।

घनी आबादी वाले क्षेत्र से 7 समपार फाटकों के समाप्त होने से सड़क एवं रेल दुर्घटनाओं की संभावना में उल्लेखनीय कमी आएगी।

समपार फाटकों के संचालन एवं रखरखाव में लगे रेलवे कर्मचारियों का बेहतर उपयोग अन्य परिचालन कार्यों में किया जा सकेगा।

जूनागढ़ नगर निगम द्वारा नए ग्रोफेड स्टेशन और वर्तमान जूनागढ़ स्टेशन के बीच ई-बस सेवा प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे मीटर गेज यात्रियों को ब्रॉड गेज ट्रेनों एवं शहर के अन्य हिस्सों तक सुविधाजनक संपर्क प्राप्त होगा।

वर्तमान जूनागढ़ स्टेशन पर मीटर गेज परिचालन समाप्त होने के बाद उपलब्ध भूमि का उपयोग ब्रॉड गेज यार्ड एवं अन्य परिचालन सुविधाओं के विस्तार हेतु किया जाएगा। रेलवे की यह पहल परिचालनिक आवश्यकता एवं नागरिक सुविधा — दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे न केवल शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि जूनागढ़ के शहरी विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

अहमदाबाद मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत व्यापक जनजागरूकता एवं स्वच्छता अभियान आयोजित

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं प्लास्टिक उपयोग में कमी लाने हेतु व्यापक जनजागरूकता अभियान एवं विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मंडल द्वारा 15.05.2026 से 05.06.2026 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। इस दौरान रेलवे कर्मचारियों, यात्रियों, संविदा कर्मियों तथा स्टॉल संचालकों को स्वच्छता एवं सतत विकास के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर 15.05.2026 से 19.05.2026 तक "स्वच्छता शपथ" कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें रेलवे कर्मचारियों एवं यात्रियों ने स्वच्छता बनाए रखने तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। यात्रियों को प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग करने एवं यात्रा के दौरान अपनी स्वयं की पानी की बोतल साथ रखने के लिए जागरूक किया गया।

रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार घोषणाएं प्रसारित कर यात्रियों को स्वच्छता बनाए रखने, प्लास्टिक उपयोग कम करने, स्वयं की पानी की बोतल उपयोग करने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। रेलवे अधिकारियों द्वारा स्टॉल संचालकों एवं विक्रेताओं को गैर-प्लास्टिक एवं पर्यावरण अनुकूल कट्लरी अपनाने हेतु परामर्श भी दिया गया। दिनांक 19.05.2026 से 22.05.2026 तक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन अभियान के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाए गए। प्लेटफॉर्मों पर कचरा पृथक्करण व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान संचालित किए गए तथा यात्रियों को कचरे के उचित निस्तारण के प्रति जागरूक किया गया। इन अभियानों में स्थानीय समुदायों एवं गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भी सहभागिता रही। रेलवे कर्मचारियों को विशेष रूप से प्लास्टिक उपयोग में कमी एवं जैविक अपशिष्ट प्रबंधन पर संवेदनशील बनाया गया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 23.05.2026 से 26.05.2026 तक "प्लास्टिक न्यूनीकरण एवं सतत प्रथाएं" विषय पर विशेष अभियान चलाए गए। रेलवे स्टेशनों पर स्थापित प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनों के रखरखाव एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। साथ ही, स्टेशनों पर विक्रेता स्टॉलों का निरीक्षण कर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के प्रभावी अनुपालन की निगरानी की गई।

रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध वॉटर कूलर सुविधाओं का निरीक्षण कर यात्रियों को अपनी बोतल पुनः भरने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे एकल उपयोग प्लास्टिक बोतलों की खपत कम हो सके। सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों से प्लास्टिक बोतलों एवं अन्य प्लास्टिक वस्तुओं के सीमित उपयोग हेतु सहयोग की अपील की गई तथा इस संबंध में यात्रियों से फीडबैक भी प्राप्त किया गया।

कैटरिंग एवं ट्रेन सेवा प्रदाताओं को वर्जिन प्लास्टिक उत्पादों के स्थान पर पुनर्चक्रित एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। गैर-सरकारी संगठनों एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से संवादात्मक कार्यक्रम आयोजित कर प्लास्टिक प्रदूषण एवं उसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने की पहल भी की गई।

इसके अतिरिक्त, विक्रेताओं एवं कर्मचारियों को दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादों की पैकेजिंग थैलियों को आंशिक रूप से काटने के संबंध में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया, ताकि माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जा सके। पर्यावरण माह के अंतर्गत स्वच्छता अभियान लगातार जारी हैं। अहमदाबाद मंडल पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं सतत विकास के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा सभी यात्रियों एवं हितधारकों से स्वच्छ एवं हरित वातावरण निर्माण में सक्रिय सहभागिता की अपील करता है।

झुलसती धूप में भी बरकरार रहे चेहरे की चमक, घरेलू नुस्खों से पाएं नैचुरल निखार -शहनाज़ हुसैन

गर्मियों का मौसम आते ही तेज धूप, उमस और प्रदूषण का असर सबसे पहले हमारी त्वचा पर दिखाई देने लगता है। खासतौर पर चेहरे की त्वचा धूप की अल्ट्रा वायलेट किरणों के संपर्क में आकर काली पड़ने लगती है, जिससे चेहरे की प्राकृतिक चमक फीकी हो जाती है। कई लोग घर से बाहर निकलते समय चेहरे को कपड़े से ढकते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं और धूप से बचने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद टैनिंग की समस्या पूरी तरह टल नहीं पाती। समुद्र तटों पर घूमने, लंबे समय तक बाहर रहने या रोजमर्रा की भागदौड़ के कारण त्वचा पर धूप का प्रभाव बढ़ जाता है और चेहरा बेजान व डल दिखने लगता है। ऐसे में लोग अक्सर बाजार में मिलने वाले महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं। हालांकि हर उत्पाद हर त्वचा के लिए उपयुक्त नहीं होता और कई बार इनसे एलर्जी, जलन या अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। सौंदर्य विशेषज्ञ शहनाज़ हुसैन के अनुसार, प्राकृतिक घरेलू उपाय त्वचा को बिना नुकसान पहुंचाए टैनिंग दूर करने और चेहरे की खोई चमक वापस लाने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। पपीता गर्मियों में त्वचा के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। यदि धूप में रहने के कारण चेहरा काला पड़ गया हो तो पका हुआ पपीता त्वचा को फिर से निखार देने में मदद करता है। इसके लिए पपीते को मैश कर उसमें नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर चेहरे पर लगाया जा सकता है। सूखने के बाद चेहरे को ताजे पानी से धो लेने पर त्वचा धीरे-धीरे साफ और मुलायम दिखने लगती है। पपीते में मौजूद प्राकृतिक एंजाइम मृत त्वचा को हटाने में मदद करते हैं, जबकि नींबू त्वचा की रंगत को हल्का करने का काम करता है। पपीते के साथ शहद का मिश्रण भी सन टैन हटाने में कारगर माना जाता है। पपीते में शहद मिलाकर बनाया गया फेस पैक त्वचा को पोषण देता है और उसे कोमल बनाए रखता है। नियमित उपयोग से चेहरे की थकी हुई त्वचा में नई चमक आने लगती है।

नींबू भी त्वचा की रंगत सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक चम्मच नींबू का रस, शहद और दूध मिलाकर तैयार किया गया मिश्रण चेहरे पर लगाने से त्वचा साफ और चमकदार दिखाई देने लगती है। दूध में मौजूद प्राकृतिक वसा और खनिज त्वचा को पोषण देते हैं, जबकि शहद त्वचा की नमी बनाए रखता है। इसी तरह चीनी और नींबू के रस से तैयार स्क्रब मृत त्वचा हटाने में सहायक होता है। इसे हल्के हाथों से चेहरे पर लगाने से त्वचा की गंदगी साफ होती है और चेहरा फ्रेश महसूस होता है।

गर्मियों में खीरा त्वचा के लिए किसी प्राकृतिक कूलेंट से कम नहीं माना जाता। इसका ठंडा और शांत प्रभाव त्वचा को तुरंत राहत देता है। खीरे का रस, गुलाब जल और नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा को ताजगी मिलती है और टैनिंग कम होने लगती है। खीरे में प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा की रंगत निखारने में मदद करते हैं। आंखों पर खीरे की स्लाइस रखने से भी थकान कम होती है और त्वचा तरोताजा महसूस करती है।

जई का आटा और मठ्ठा भी गर्मियों में त्वचा को साफ और मुलायम बनाए रखने के लिए उपयोगी घरेलू उपाय माने जाते हैं। दोनों को मिलाकर तैयार पेस्ट चेहरे पर लगाने से त्वचा की गहराई से सफाई होती है और अतिरिक्त तेल हटता है। वहीं केला, शहद और ऑलिव ऑयल का मिश्रण त्वचा को गहराई से मॉइश्चराइज करता है। यह फेस पैक खासतौर पर रूखी और धूप से प्रभावित त्वचा के लिए लाभकारी माना जाता है।

एलोवेरा को त्वचा के लिए प्राकृतिक वरदान माना जाता है। एलोवेरा जेल में हल्दी और शहद मिलाकर लगाया जाए तो यह त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ टैनिंग कम करने में मदद करता है। एलोवेरा त्वचा को हाइड्रेट रखता है और उसकी प्राकृतिक चमक बनाए रखने में सहायक होता है। विशेषज्ञों के अनुसार रोजाना थोड़ी मात्रा में एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा की रंगत धीरे-धीरे साफ होने लगती है।

बेसन, दही और हल्दी का पारंपरिक उबटन भी गर्मियों में बेहद प्रभावी माना जाता है। बेसन त्वचा की गंदगी साफ करता है, दही त्वचा को मुलायम बनाता है और हल्दी प्राकृतिक एंटीसेप्टिक का काम करती है। यह मिश्रण त्वचा को साफ, चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। एक अन्य प्रभावी घरेलू फेस पैक में कद्दूकस किया हुआ खीरा, कच्चा दूध, एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाया जाता है। यह पैक त्वचा को गहराई से ठंडक देता है और नियमित उपयोग से धीरे-धीरे टैनिंग कम होने लगती है। त्वचा विशेषज्ञों का कहना है कि केवल फेस पैक लगाना ही काफी नहीं होता, बल्कि त्वचा की नियमित देखभाल भी जरूरी है। दिन में दो से तीन बार चेहरे को ठंडे पानी से धोने से धूल, पसीना और गंदगी साफ होती है। सप्ताह में एक या दो बार हल्का स्क्रब करने से डेड स्किन हटती है और चेहरे पर प्राकृतिक ग्लो आता है। हालांकि स्क्रब करते समय चेहरे को ज्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।इसके अलावा गर्मियों में त्वचा को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। दिन में दो बार मॉइश्चराइजर लगाने से त्वचा की नमी बनी रहती है और रूखापन कम होता है। पर्याप्त पानी पीना, संतुलित आहार लेना और तेज धूप में निकलते समय चेहरे को ढकना भी त्वचा की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है।

अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के पास न्यू मेंटल कैंपस में 105 करोड़ रुपए के खर्च से अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्टल और कैंटीन ब्लॉक बनाए जाएंगे : स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया

अहमदाबाद विमान दुर्घटना में हुए 'अतुल्यम 1 से 4 ब्लॉक' के नुकसान के एवज में टाटा एयरलाइंस स्वास्थ्य विभाग को 53.12 करोड़ रुपए चुकाएगी : स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया

गांधीनगर : स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया ने कहा कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना में सिविल हॉस्पिटल-असारवा के पास स्थित न्यू मेंटल कैंपस में हुए 'अतुल्यम 1 से 4 ब्लॉक' के नुकसान के एवज में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टाटा एयरलाइंस से 53.12 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। जिसके संदर्भ में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए टाटा एयरलाइंस आगामी समय में स्वास्थ्य विभाग को 53.12 करोड़ रुपए की पूरी राशि चुकाएगी।

इस संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया ने कहा कि गत 12 जून 2025 को मेघाणीनगर में हुई अहमदाबाद प्लेन क्रैश विमान दुर्घटना के कारण स्वास्थ्य विभाग के अधीन 'अतुल्यम 1 से 4' ब्लॉक, कैंटीन और सब-स्टेशन बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ था। दुर्घटना के समय इस हॉस्टल में कुल 92 विद्यार्थी रह रहे थे। विमान दुर्घटना के बाद किए गए स्ट्रक्चरल ऑडिट में इन बिल्डिंग्स को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किए जाने के कारण उन्हें तोड़ने की मजबूरी बनी। ऐसे में विद्यार्थियों की रहने की सुविधा बाधित न हो और उनके हित में तत्काल नया हॉस्टल बनाने का निर्णय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

सिविल अस्पताल कैंपस के पास बनने वाले नए आधुनिक हॉस्टल के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल-असारवा के पास स्थित न्यू मेंटल कैंपस में डॉक्टरों के लिए अनुमानित 105 करोड़ रुपए के खर्च से नया अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी मैरिड पीजी हॉस्टल बनाया जाएगा। मेडिकल क्षेत्र में सुपर स्पेशियलिटी की नई 48 सीटों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आगामी तीन वर्षों के कुल 144 विद्यार्थियों सहित कुल 236 सुपर स्पेशियलिटी मैरिड पीजी डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था की गई है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत न्यू मेंटल कैंपस-आईजीपी कंपाउंड, मेघाणीनगर में नए सुपर स्पेशियलिटी हॉस्टल ब्लॉक के अलावा एक आधुनिक कैंटीन ब्लॉक और नया सब-स्टेशन बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त जमीन भी आवंटित कर दी गई है।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया ने आगे कहा कि इस कार्य को अधिक गति देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में अनुमानित 51.84 करोड़ रुपए की राशि के मुकाबले 34.65 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था मंजूर की गई है। आगामी समय में भी स्वास्थ्य क्षेत्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।

अतुल्यम हॉस्टल की संरचना

नव नियोजित 'अतुल्यम 1 से 7' पीजी हॉस्टल जी+8 मंजिला संरचना के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 236 सुपर स्पेशियलिटी मैरिड पीजी डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक फ्लैट को स्टूडियो अपार्टमेंट शैली में तैयार किया जाएगा, जिसमें एक लिविंग रूम-अटैच किचन, एक बेडरूम और टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा सुरक्षा और प्राथमिक सुविधाओं जैसे फायर फाइटिंग सिस्टम, आरओ प्लांट और सुदृढ़ ड्रेनेज व्यवस्था का भी समावेश किया गया है।

विद्यार्थियों की सुख सुविधाओं के लिए हॉस्टल कैंपस में पार्किंग हेतु विशाल बेसमेंट तथा अविवाहित पीजी विद्यार्थियों के लिए अलग आवास, अत्याधुनिक मेस, जिम, रिक्रिएशन रूम और आकर्षक लैंडस्केपिंग जैसी सुविधाओं की भी योजना बनाई गई है।

सरखेज-धोलेरा नई सेमी हाई स्पीड रेलवे ब्रॉड गेज डबल लाइन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु बैठक का आयोजन

पश्चिम रेलवे अहमदाबाद की सर्वे एवं निर्माण संस्था को सरखेज-धोलेरा नई सेमी हाई स्पीड रेलवे ब्रॉड गेज डबल लाइन परियोजना के साथ-साथ लोथल स्थित नेशनल मैरीटाइम हैरिटेज कॉम्पलेक्स (NMHC) एवं धोलेरा एयरपोर्ट तक ब्रांच लाइन निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगभग 134 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण 220 किमी प्रति घंटा की डिज़ाइन स्पीड के अनुरूप किया जाएगा।

परियोजना के सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे द्वारा निर्माण निविदा में रुचि रखने वाले सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा S & T (सिग्नल एवं दूरसंचार) क्षेत्र के संभावित बीडर्स/कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है।

यह बैठक दिनांक 28 मई 2026 (गुरुवार) को प्रातः 11:30 बजे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) कार्यालय, 2nd फ्लोर, निर्माण भवन, नरोडा रोड, जीएससी हॉस्पिटल के सामने, असारवा अहमदाबाद में आयोजित होगी। इस बैठक में परियोजना के कार्यान्वयन, पैकेजिंग एवं तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

सभी इच्छुक एवं संभावित बीडर्स/कॉन्ट्रैक्टर्स से अनुरोध है कि वे अपने मूल्यवान सुझावों एवं विचारों के साथ बैठक में व्यक्तिगत रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से सहभागिता सुनिश्चित करें।